

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
20.12.2023 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2775 का उत्तर

खामगांव-जालना रेल मार्ग को पूरा करना

2775. श्री प्रतापराव जाधव:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या महाराष्ट्र के बुलढाणा क्षेत्र में खामगांव-जालना तक रेल मार्ग की अंतिम अवस्थिति के संबंध में सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या इस संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रेलवे को प्रस्तुत कर दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह सच है कि वर्ष 2004 में शुरू किए जाने और सभी औपचारिकताएं पूरी कर लिए जाने के बावजूद यह परियोजना अभी भी रेलवे बोर्ड के पास लंबित है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बुलढाणा के लोग इस रेल मार्ग के पूरा न होने के कारण बहुत कष्ट उठा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) उक्त मार्ग को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

खामगांव-जालना रेल मार्ग को पूरा करने के संबंध में दिनांक 20.12.2023 को लोक सभा में श्री प्रतापराव जाधव, श्री सुधीर गुप्ता, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक और श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे के अतारांकित प्रश्न सं. 2775 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (च): महाराष्ट्र राज्य में जालना - खामगांव नई लाइन (155 किलोमीटर) के लिए अंतिम स्थान-निर्धारण सर्वेक्षण स्वीकृत किया गया है। सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है।

इसके अलावा, दिनांक 01.04.2023 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशतः स्थित 80,184 करोड़ रुपये की लागत पर कुल 5,872 किलोमीटर लंबाई की 34 रेल अवसंरचना परियोजनाएं (16 नई लाइन, 02 आमान परिवर्तन और 16 दोहरीकरण) योजना बनाने/अनुमोदन/निर्माण के चरणों में हैं, जिनमें से 1,421 किलोमीटर लंबाई को चालू कर दिया गया है और मार्च 2023 तक 23,964 करोड़ रुपये का व्यय उपगत किया गया है। इनमें शामिल हैं:-

- (i) 38,423 करोड़ रुपये की लागत पर कुल 2,017 किलोमीटर लंबाई की 16 नई लाइन परियोजनाएं जिनमें से मार्च 2023 तक 93 किलोमीटर लंबाई को चालू कर दिया गया है और 6,052 करोड़ रुपये का व्यय उपगत किया गया है।
- (ii) 7,339 करोड़ रुपये की लागत पर कुल 580 किलोमीटर लंबाई की 2 आमान परिवर्तन परियोजनाएं जिनमें से मार्च 2023 तक 283 किलोमीटर लंबाई को चालू कर दिया गया है और 2,791 करोड़ रुपये का व्यय उपगत किया गया है।
- (iii) 34,422 करोड़ रुपये की लागत पर कुल 3,275 किलोमीटर लंबाई की 16 दोहरीकरण परियोजनाएं जिनमें से मार्च 2023 तक 1,045 किलोमीटर लंबाई को चालू कर दिया गया है और 15,121 करोड़ रुपये का व्यय उपगत किया गया है।

2014 से, भारतीय रेल में सर्वत्र निधि आवंटन और तदनु रूप परियोजनाओं को चालू करने में काफी वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशतः स्थित रेल अवसंरचना परियोजनाओं एवं संरक्षा कार्यों के लिए बजट आवंटन इस प्रकार है:-

अवधि	औसत परिव्यय	2009-14 के दौरान औसत आवंटन की तुलना में प्रतिशत अधिकता
2009-14	₹ 1,171 करोड़/वर्ष	-
2023-24	₹ 13,539 करोड़	1056% अधिक

2014-23 के दौरान, महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशतः स्थित 1,472 किलोमीटर रेलखंड (147 किलोमीटर नई लाइन, 136 किलोमीटर आमाम परिवर्तन और 1189 किलोमीटर दोहरीकरण) को प्रति वर्ष 163.56 किलोमीटर की औसत दर से चालू किया गया है, जो 2009-14 के दौरान चालू करने की औसत दर (प्रति वर्ष 58.4 किलोमीटर) से 180% अधिक है।

पिछले तीन वर्षों (2020-21, 2021-22 और 2022-23) और चालू वित्त वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशतः स्थित कुल 74 सर्वेक्षण (14 नई लाइन, 02 आमाम परिवर्तन और 58 दोहरीकरण) स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी कुल लंबाई 5,719 किलोमीटर है।

रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृतियां, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक परिस्थिति, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना (परियोजनाओं) को पूरा करने के समय को प्रभावित करते हैं।

रेल परियोजनाओं के कारगर और त्वरित कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाये गए विभिन्न कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं- (i) निधियों के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि, (ii) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन, (iii) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी, (iv) त्वरित भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव स्वीकृतियों और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों के साथ नियमित अनुवर्तन।
